धन की कमी के बावजूद ऋण लेकर अकाल पीड़ितों को राहत- गहलोत

वीडियो कान्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री रूबरू

[कार्यालय संवाददाता]

जयपुर, 30 मई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में अकाल की विभीषिका से निपटने के लिए धन की कमी होने के बावजूद राज्य सरकार ऋण लेकर प्रभावितों को राहत पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य ने केन्द्र सरकार से राजस्थान को विशेष रूप से राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से मदद करने का अनुरोध किया था किन्तु केन्द्र ने पर्याप्त राशि आवंटित नहीं की।

गहलोत मंगलवार को यहां शासन सचिवालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मसूरी में बैठे भारतीय सेवा के प्रशिक्षुओं तथा जैसलमेर से 70 किलोमीटर दूर फतेहगढ़ ग्राम पंचायत की ग्रामसभा में बैठे जिला कलक्टर, पंच-सरपंच तथा ग्रामीणों से रूबरू होकर उनके सीधे संवादों का जवाब दे रहे थे। इस तकनीक के तहत जयपुर, मसूरी एवं जैसलमेर में एस.सी.पी.सी.वी. सेट [वेरी स्माल एपरचर टर्मिनल] स्थापित कर उपग्रह के माध्यम से जोड़े गए थे। इसका स्विचिंग दिल्ली स्थित केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष द्वारा किया जा रहा था, जिसके माध्यम से वीडियो एवं श्रव्य सिगनल्स से आदान-प्रदान सम्पादित किया गया।

प्रशिक्षुओं ने मुख्यमंत्री तथा जिला कलक्टर, सरपंच व ग्रामीणों से राज्य में अकाल की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों तथा अकाल प्रभावित लोगों व पशुओं को पहुंचाई जा रही राहत के बारे में सवाल किए। यह वीडियो कान्फ्रेसिंग राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय के सहयोग से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी एवं राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, भारत सरकार द्वारा आयोजित की गई थी। मसूरी से अकादमी के निदेशक बी.एस. बासवान एवं पाठ्यक्रम समन्वयक यदुवेन्द्र माथुर तथा 1999 बैच के 53 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चारे की कमी वाले जिलों में पशु शिविर संचालित किए जा रहे हैं। बड़े पशु के लिए दस रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी एक जून से अकाल राहत कार्यों पर 17 लाख 50 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 87-88 में जब राजस्थान अकाल से भयंकर त्रस्त था उस समय को छोड़कर इतनी बड़ी तादाद में कभी भी राहत कार्यों पर श्रमिकों को रोजगार सुलभ नहीं कराया गया। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कोई भी बारहमासी नदी नहीं है वहां का जन जीवन वर्षा पर निर्भर करता है। सिंचाई के साधन अपर्याप्त है, ऐसी स्थिति में नर्मदा नदी का पानी बाड़मेर व जालौर तक ले जाने का विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पुनः पत्र लिखकर 700 करोड़ रुपए की मांग की है तथा श्रमिकों को ''काम के बदले अनाज योजना'' के तहत दिए जाने वाले गेहूं को अनुदान के रूप में देने की मांग की है।